योजना, बारहवीं योजना, तेरहवीं योजना तक की आप बात कर रहे हैं, मेरा आपसे मूल प्रश्न यह है कि इन सबके लिए आपके पास फंड्स की क्या व्यवस्था है? दूसरा मेरा 'ब' प्रश्न यह है कि तीन दिन पहले आपने यहां इसी सदन में यह कहा था कि वर्ष 2012 तक गांव गांव में, घर घर में बिजली होगी, लेकिन उसमें आप एक बात भूल गए थे खेत खेत में बिजली। यह खेत खेत में बिजली की बात आपने नहीं कही थी और यदि यह खेत खेत में बिजली नहीं होगी तो देश बहुत पीछे रह जाएगा। तो इस दिशा में एन०टी०पी०सी० और जो दूसरे जितने भी आपके समकक्ष उपक्रम हैं उन सबके लिए आपके पास क्या कोई समग्र-रूपेण योजना बिजली की है या नहीं क्योंकि आपको एक लाख मेगावाट बिजली आने वाले दस वर्षों में चाहिए? इस बारे में अगर आप स्पष्ट स्थिति बताने की कृपया करेंगे तो हम पर उपकार होगा। धन्यवाद।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, एन०टी०पी०सी० को जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहां तक धन की आवश्यकता का जो सवाल है, निश्चित रूप से घर की कमी नहीं आएगी, एन०टी०पी०सी० अपने बलबूते पर इन सारी परियोजनाओं को पूरा कर सकता है। दूसरा, जहां तक खेत खेत में बिजली पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं, तो जब हम घर घर तक बिजली पहुंचाने की सोचते हैं तो निश्चित रूप से खेत खेत तक भी बिजली वर्ष 2012 तक पहुंच जाएगी।

श्री सभापति: इनके खेत और घर, दोनों देख लीजिए।

Mineral deposits in Orissa

*128. SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA : Will the Minister of MINES be pleased to state :

(a) the estimated total mineral deposits in Orissa and how many mines are under the control of Government undertakings and how many of them have been given to private companies; and

(b) whether Government propose to lease more mines in Orissa to private companies; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI RAMESH BAIS) : (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The estimated total mineral reserves of some of the important non fuel minerals in Orissa are given below :

(in million tonnes)

Minerals	Total Reserves
Iron Ore	4177
Chromite	111
Manganese Ore	116
Limestone	2224
Bauxite	1530
Dolomite	882

As per the information received from the Indian Bureau of Mines, a subordinate office under the administrative control of the Ministry of Mines, a total of 234 number of mines have reported to IBM during 2002-2003. Out of this 64 mines are in the public sector and 170 are in the private sector.

(b) Mineral Concessions are granted by the State Governments under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and Rules made thereunder. However only for minerals specified under the First Schedule to the aforesaid Act, prior approval of the Central Government is required before grant of mineral concessions by the State Governments. As per the National Mineral Policy 1993, the exploration and exploitation of all non fuel non atomic minerals have been thrown open to private investment and therefore commercial exploitation of minerals take place as per economic viability of the mineral concerned.

श्री बालकवि बैरागी: सभापति जी, अभी रमेश बैस साहब, मंत्री जी जो भी उत्तर देंगे बहुत उमंग से देंगे और भावात्मक उत्तर दिए जाएंगे। हमारा अनुरोध है कि आप यथार्थ में उत्तर देने की कृपा करें।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, the hon. Minister, his answer, has stated that out of 234 mines in Orissa, 64 mines belong to the public sector and 170 mines belong to the private sector. The hon. Minister has also stated that as per the National Mineral Policy 1993, they are giving more emphasis to the private sector. So, my question is whether it is a fact that in Orissa public sector companies like the Orissa Mining Corporation, which is doing very well and earning a good profit, had asked for mines; the Industrial Development Corporation had asked for mines; the Central public sector companies, like the NTPC and the Coal India had asked for mines, but still instead of giving mines to the Central Public Sector companies and the State Public Sector companies, more emphasis is being given to give mines to the private sector. Then the Orissa Government has once stipulated that those private sector companies, who take mines on lease in Orissa, will have to establish factories in the State of Orissa, otherwise they would not be given mines on lease.

श्री रमेश बैस: सभापति जी, कोई भी माइनिंग लीज पर देने का काम राज्य सरकार का होता है क्योंकि राज्य सरकार उसकी मालिक होती है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है। नियम में है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो भी संस्थाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन राज्य सरकार जैसा प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजती है, उसी के अनुसार हम उसको सैंक्शन करते हैं। राज्य सरकार अगर वहां के निगम के लिए लीज के लिए आवेदन करेगी तो वह राज्य मान्य कारपोरेशन को देंगे, अगर प्राइवेट सैक्टर के लिए कहेगी तो उसे देंगे क्योंकि उदारीकरण को देखते हुए केन्द्र सरकार ने नीति बनाई है और जो प्राइवेट सैक्टर में अलाऊ नहीं था, उसको भी अलाऊ किया गया है। जो राज्य सरकार जिसके बारे में प्रस्ताव करती है, हम उसकी छान-बीन करके राज्य सरकार को वापिस भेज देते हैं क्योंकि लीज़ देने का काम राज्य सरकार का होता है।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, the reply given by the hon. Minister is that the total reserve of Chromite in Orissa is 111 million tones. Sir, that is about 90 per cent of the total deposits in the country. Such valuable deposits of minerals Orissa has! But, unforunately, if you look at the figures, right after independence till today, you will find that investment in Orissa has been very poor. No, investment has been done; neither from the Central Public Sector nor from the State Public Sector.

It is being seen that mines are being sold. A major portion of Orissa consists of forests and mines only. If in the name of liberalisation, in the name of encouraging private entrepreneurs, all mines and forests are given on lease, then, the whole of Orissa would be on lease.

My last point is this. As you all know, work in the Orissa Assembly was stalled because of this mining lease controversy. The Judeo tape issue also came into the limelight in the country. I would like to know whether there is any secret deal between the State Government and the Central Government to give Chromite the Bauxite mines on lease to Australian multinational companies or to some other multi-national companies and to sell all the mines of Orissa. I want to know whether there is any secret deal in it.

श्री रमेश बैस: सभापति जी, उड़ीसा में सरकार के द्वारा ''नाल्को'' भी चलाई जा रही है, ''क्रोम'' की भी है, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है कि प्राइवेट सैक्टर में सारे दिए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को नहीं दिए जा रहे हैं, तो माननीय सदस्य को चाहिए कि वे राज्य सरकार को इस बारे में लिखें क्योंकि प्राइवेट सैक्टर को देना या न देना, यह राज्य सरकार के अधीन में आता है। अगर वे प्रस्ताव नहीं भेजेंगे तो हम नहीं देंगे क्योंकि इसमें हम सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)...

श्री रामचन्द्र खूंटिया: तीन दिन उड़ीसा की असेम्बली चल नहीं पाई और बोलते है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सीधा सा प्रश्न है कि आप क्या यह चाहेंगे कि बिना स्टेट की अनुमति के ये कुछ कार्रवाई उसमें कर लें? ...(व्यवधान)...

श्री रामचन्द्र खूंटिया: स्टेट गवर्नमेंट सैंट्रल गवर्नमेंट को लीज़ ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, नहीं। वह छोडिए। आप बैठिए, बैठ जाइए।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, I want your protection... (*Interruption*). We want your protection.

श्री सभापति। मैं क्या प्रोटेक्शन दूं। श्री सुरेन्द्र लाठ।

श्री सुरेन्द्र लाठ: माननीय सभापति जी, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि ये जो माइंस दी जाती हैं यह राज्य सरकार के अंडर आता है और राज्य सरकार की रिकमेंडेशंस के बाद ही ये उस पर कार्रवाई करते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई गाइडलाइंस बनाई गई हैं माइंस अलॉटमेंट के लिए और गत तीन वर्षों में प्राइवेट एंटरप्रिन्योर्स को उड़ीसा में कितनी आयरन ओर दी हैं? क्या उड़ीसा सरकार का केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई है कि जो कंज्यूमर है,

केवल उन्हीं को माइन्स दी जाती हैं या उसके बाहर भी किसी को माइंस दी जाती हैं, क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान है?

श्री रमेश बैस: सभापति जी, किसी भी खान की स्वीकृति के लिए नियम बने हुए हैं, समय-समय पर आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन भी किए गए हैं। किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव आता है, जब तक उसमें माइनिंग प्लान नहीं होता जिसे कि आई॰सी॰एम॰, जो कि एक सरकारी संस्था है, बनाती है और स्वीकृति करती है, हम उस पर कोई विचार नहीं करते। आई॰सी॰एम॰ की स्वीकृति के बाद भी जो माइनिंग के लिए आवेदन आते है, उन पर विचार किया जाता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उदारीकरण नीति को अपनाते हुए हमने निजी क्षेत्र के लिए कुछ चीजें खोल दी हैं और उड़ीसा सरकार के द्वारा जितने प्रस्ताव आए है, उनमें 173 खानों को हमने निजी क्षेत्र में अनुमति दी हैं।

Modernisation of police by Andhra Pradesh

*129 DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRI RUMANDLA RAAMACHANDRAYYA: ††
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the requests made by the Andhra Pradesh Government for sanctioning of equipment for police modernisation;

(b) since when the request has been pending; and

(c) by when a final decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHR I.D. SWAMI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The annual Central allocation for Anhdra Pradesh under the Scheme for Modernisation of State Police Forces (MPF Scheme) was fixed at Rs. 82 crore, with annual plan size being Rs. 164.00 crores from 2000-01. The balance 50% was to be provided by the State Government. The information pertaining to approved plans, Central assistance released and utilization reported by the State Government of Andhra Pradesh pertaining to 2000-01 to 2002-03 is as under :

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rumandla Raama Chandrayya